व्यक्तिगत विवरण

नाम.....

माता/पिता का नाम.....

कार्यालय का पता.....

घर का पता.....

दूरभाष नं. (कार्यालय).....

दूरभाष नं. (घर).....

मोबाइल नं.....

आधार कार्ड नं.....

बैंक खाता नं.....

ई-मेल.....

ड्राइविंग लाईसैंस नं.....

रक्त समूह.....

प्रदेश में भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए तुरन्त सम्पर्क करें

टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर : 1064

या

टोल फ्री नम्बर : 1800-180-2022 या वहाट्सअप नम्बर : 9417891064

बदरपुर-मु
श्री नरेन्द्र मोदी

	नाम एवं पद	दूरभाष		निवास पता
	मंत्री परिषद्			
	मनोहर लाल मुख्यमंत्री (चौथी मंजिल, सचिवालय)	0172-2749396 0172-2749409	2749394 2749395	1/3
	राम बिलास शर्मा (शिक्षा मंत्री) (कमरा नं0 32/8, सचिवालय)	0172-2740793	2742032	32/3
	कैप्टन अभिमन्यु (वित्त मंत्री) (कमरा नं0 40/5, सचिवालय)	0172-2740212	2741280	48/2
	ओम प्रकाश धनखड़ (कृषि मंत्री) (कमरा नं0 34/8, सचिवालय)	0172-2740010	2742049	49/2
	अनिल विज (स्वास्थ्य मंत्री) (कमरा नं0 49/8, सचिवालय)	0172-2740157	9416211001	2153/63
	नरबीर सिंह (लोक निर्माण मंत्री) (कमरा नं0 39/8, सचिवालय)	0172-2740231	2540098	239/16
	कविता जैन (शहरी स्थानीय निकाय मंत्री) (कमरा नं0 43–ए/8, सचिवालय)	0172-2740833	2790777	75/7
	कृष्ण लाल पंवार (परिवहन मंत्री) (कमरा नं0 24/8, सचिवालय)	0172-2740906	2795108	79/7
	विपुल गोयल (उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री) (कमरा नं0 42/6, सचिवालय)	0172-2743709	2794473	70/7

नाम एवं पद	दूरभाष		निवास पता

राज्य मंत्री

मनीष कुमार ग्रोवर — 0172-2740867 — 2794617 — 73/7
(सहकारिता, स्वतंत्र प्रभार)
(कमरा नं0 43–सी/8, सचिवालय)

कृष्ण कुमार बेदी — 0172-2740358 — 2791823 — 68/7
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वतंत्र प्रभार)
(कमरा नं0 31/8, सचिवालय)

कर्ण देव काम्बोज — 0172-2740195 — 2792072 — 72/7
(खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, स्वतंत्र प्रभार)
(कमरा नं0 47/8, सचिवालय)

डॉ. बनवारी लाल — 0172-2740794 — 2741061 — 52/5
(जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, स्वतंत्र प्रभार)
(कमरा नं0 29/8, सचिवालय)

नायब सिंह — 0172-2740523 — 2793155 — 76/7
(श्रम एवं रोजगार, स्वतंत्र प्रभार)
(कमरा नं0 44बी/6, सचिवालय)

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ
1.	किसान हैं हमारी पहचान	1
2.	सहकारी समितियों के जरिए किसानों को मदद	2
3.	बागवानी फसलों से आमदनी में वृद्धि	3
4.	किसानों को सुविधायें	4
5.	आखिरी छोर तक नहर का पानी	5
6.	सहकारी चीनी मिलों का सुदृढ़ीकरण	6
7.	पशुधन संवर्धन एवं संरक्षण	7
8.	दूध-दही का खाणा-म्हारा देस हरियाणा	8
9.	डिज़िटल हरियाणा	9
10.	सूचना प्रौद्योगिकी से हरियाणा की नई पहचान	10
11.	'स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत' बना जन-जन का अभियान	11
12.	गांवों का 'स्मार्ट' विकास	12
13.	नैतिक स्कूली शिक्षा, मजबूत आधार	13
14.	बेहतर उच्चतर शिक्षा से उज्ज्वल भविष्य की ओर	14
15.	युवाओं का कौशल विकास	15
16.	हरा-भरा म्हारा हरियाणा	16
17.	वन्य प्राणियों का संरक्षण	16
18.	स्वच्छ जल-सबका अधिकार	17
19.	बिजली आपूर्ति में सुधार एवं बढ़ोतरी	17-18
20.	सौर ऊर्जा-बेहतर विकल्प	19
21.	उद्योगों का हो रहा तीव्र विकास	22

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ
22.	विदेशी निवेश आकर्षित	23
23.	व्यापारियों के लिए ई-सेवायें एवं राहतें	24
24.	हरियाणा परिवहन-शान की सवारी	25
25.	एक्सप्रेस-वे एवं सड़कों का बिछा जाल	26
26.	आधुनिक एवं सुगम मैट्रो, रेल एवं हवाई सेवायें	27
27.	निरोगी काया, स्वस्थ जीवन का आधार	28
28.	चिकित्सा शिक्षा का हब बना हरियाणा	29
29.	हर जन का सपना-बने घर अपना	30
30.	अंत्योदय दर्शनःगरीबों का कल्याण	31
31.	बेटियों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण के अनूठे प्रयास	32
32.	सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखायः	33-34
33.	खेलों में दम दिखाया, हरियाणा का नाम चमकाया	35
34.	पर्यटन क्षेत्र में उभरता हरियाणा	36
35.	समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण	36
36.	देश के रक्षकों का सम्मान	37
37.	रोजगार के नये आयाम	38
38.	श्रमिकों का कल्याण एवं सम्मान	39
39.	सुदृढ़ पुलिस बल एवं कानून व्यवस्था	40
40.	भ्रष्टाचार पर लगा अंकुश, हर नागरिक हुआ खुश	41
41.	अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता व पारदर्शिता	42
42.	कर्मठता के प्रतीक कर्मचारी	42

किसान हैं हमारी पहचान

मुआवजा दरों में बढ़ोतरी

- प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए न्यूनतम 500 रुपये का मुआवजा छोटे से छोटे हिस्सेदार को भी।
- जिन क्षेत्रों में फसलें 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई, उन क्षेत्रों में एक वर्ष के लिए किसानों के कृषि के बिल शत-प्रतिशत माफ।
- जिन क्षेत्रों में फसलें 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक खराब हुई, उन क्षेत्रों में किसानों के ट्यूबवैल के बिल 50 प्रतिशत माफ।
- 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (2017-18) के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये।
- लगभग 229 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत किसानों को वितरित।
- खरीफ फसलों जैसे धान, बाजरा, मक्का व कपास के लिए प्रीमियम दर अधिकतम 2 प्रतिशत, रबी फसलों जैसे गेहूँ, जौं, सरसों व चना के लिए अधिकतम 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत तय।
- कपास की फसल पर अन्य खरीफ फसलों के समान 2 प्रतिशत ही अधिकतम प्रीमियम के साथ अतिरिक्त 3 प्रतिशत का भुगतान।
- प्याज के बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.agriharyana.nic.in
2. दूरभाषः— 0172—2570662

क्षतिग्रस्त फसलों के लिए
2403.55 करोड़ रुपये
मुआवजा राशि किसानों को वितरित

12,000 रुपये प्रति एकड़
खराब फसलों हेतु
मुआवजा राशि

सहकारी समितियों के जरिए किसानों को मदद

- समय पर अदायगी करने वाले किसानों को सहकारी ऋण ब्याज रहित।
- हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को वित्त वर्ष 2015-16 व 2016-17 में क्रमशः 100-100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
- वर्ष 2016-17 में गेहूं का उत्पादन 118 लाख 44 हजार टन तथा धान का उत्पादन 63 लाख 43 हजार टन हुआ।
- कई वर्षों के बाद बाजरे की सरकारी खरीद शुरू।

खाद्यान्नों की ई-खरीद

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य पूर्व में (रुपये-प्रति क्विंटल)	न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान में (रुपये-प्रति क्विंटल)
गन्ना	310	320
गेहूं	1525	1625
चना	3425	4000
सूरजमुखी	3300	3700

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.rcsharyana.gov.in
2. दूरभाषः— 0172—2583438

22175.20 करोड़ रुपये

किसानों को फसली ऋण

प्रदेश के इतिहास में पहली बार

मूंग की सरकारी खरीद

बागवानी फसलों से आमदनी में वृद्धि

- बागवानी क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने के लिये वर्ष 2016 में हरियाणा को "Best Horticulture State Award"।
- अंजनथली (करनाल) में 'महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय' स्थापित किया जा रहा है।
- शामगढ़ (करनाल) में 4.25 करोड़ रुपये की लागत से उद्यान बायो तकनीकी केन्द्र तथा लाडवा (कुरुक्षेत्र) में 9.10 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए उपोषण फल केन्द्र शुरू।
- स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अन्तर्गत शिवालिक विकास हेतु 2.92 करोड़ रुपये तथा फार्म व विपणन हेतु 93.02 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- सात नये उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित होंगे - होडल (पलवल), सुन्द्राह (महेन्द्रगढ़), नूंह (मेवात), मुरथल (सोनीपत), बरवाला (हिसार), भूना (फतेहाबाद) एवं रेवाड़ी। होडल (पलवल) में काम शुरू।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.hortharyana.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2582322

'बागवानी विजन'

वर्ष 2030 तक
बागवानी क्षेत्र दोगुणा, उत्पादन तिगुणा

3 क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र

बख्तावरपुर–रयया (झज्जर)
चानसोली (अम्बाला)
राजकीय बाग एवं नर्सरी (जीन्द)

'हरियाणा फ्रैश'

ब्रांड शुरू

और जल्द ही बनेंगे 340 बागवानी ग्राम

किसानों को सुविधायें

- किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ताजा फल एवं सब्जियां उपलब्ध करवाने के लिए पंचकूला सैक्टर-20 में 'किसान बाजार' शुरू।
- प्रथम चरण में प्रदेश की 54 अनाज मण्डियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल (e-NAM) से जोड़ा गया।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.agriharyana.nic.in
2. दूरभाष:– 0172–2570662

किसानों को सस्ती दरों पर

बिजली आपूर्ति

कृषक उपहार योजना

किसानों को

12 करोड़ रुपये

तक के ईनाम

और जल्द ही दूसरे चरण में प्रदेश की शेष अनाज मण्डियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल (e-NAM) से जोड़ा जाएगा।

आखिरी छोर तक नहर का पानी

- टेल तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों की मरम्मत और सफाई पर 135 करोड़ रुपये खर्च।
- वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में लगभग 125 नहरों के पुनर्वास की कार्य योजना तैयार।
- 39 वर्षों बाद पहली बार दक्षिण हरियाणा के हसनपुर दनचौली माइनरों में पहुंचाया नहरी पानी।
- मानसून ऋतु में यमुना नदी में उपलब्ध अतिरिक्त पानी को राज्य में उपयोग करने के लिए दक्षिणी यमुना नहर प्रणाली की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना तैयार।
- बाढ़ के पानी से सिंचाई और भू-जल संरक्षण के लिए 6.41 करोड़ रुपये की लागत से 390 इंजेक्शन कुएं तैयार करने का कार्य प्रगति पर।
- कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर को ताजा पानी उपलब्ध करवाने के लिए 16 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना शुरू।
- 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.hid.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2582541

हर खेत को पानी
143 करोड़ रुपये की
परियोजना स्वीकृत

564 जलमार्गों के पुनर्वास हेतु
300 करोड़ रुपये की
परियोजना स्वीकृत

सतलुज-यमुना लिंक नहर
हरियाणा अपने वैध हिस्से का
पानी लेने के लिए **कृत-संकल्प**

सहकारी चीनी मिलों का सुदृढ़ीकरण

- करनाल सहकारी चीनी मिल का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- वर्ष 2016-17 के दौरान सहकारी चीनी मिलों को ऋण प्रदान करने के लिए 315 करोड़ रुपये का प्रावधान, जिसमें से 252 करोड़ रुपये गन्ना राशि के भुगतान हेतु उपलब्ध करवाए।
- पानीपत की वर्तमान चीनी मिल गांव डाहर में स्थानान्तरित होगी।
- शुगरफैड और सहकारी चीनी मिलों में E-Procurement शुरू ।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.haryanasugerfed.com
2. दूरभाषः– 0172–2590824

गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य
320 रुपये प्रति क्विंटल तक
जो देशभर में सर्वाधिक

सभी 10 सहकारी चीनी मिलों के लिए
सघन गन्ना विकास योजना
स्वीकृत

पशुधन संवर्धन एवं संरक्षण

- अवैध गौ-तस्करी करने वाले व्यक्ति को सात वर्ष तक की कैद एवं उस अवैध वाहन को जब्त करने के अतिरिक्त 70 हजार रुपये तक का जुर्माना।
- जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक साल तक की अतिरिक्त कैद की सजा।
- बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए हिसार तथा पानीपत जिलों में गौ-अभ्यारण्य स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू।
- एकीकृत पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत देशी/संकर नस्ल के दुधारु पशु, बकरी, भेड़, शूकर, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट आदि की बीमा सुविधा।
- पशुओं की चिकित्सा सुविधा के लिए 797 वी.एल.डी.ए. व 246 पशु चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है।
- मोबाइल पशु चिकित्सा एवं रोग निदान प्रयोगशालाओं के माध्यम से पशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य जांच का उचित विस्तार जिला स्तर से खण्ड स्तर तक सम्भव हो पाएगा।
- राज्य में पहली बार देसी गायों की सौन्दर्य प्रतियोगिता का आयोजन गांव बहुअकबरपुर (रोहतक) में किया गया।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.pashudhanharyana.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2574662

हरियाणा गौ-वंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम-2015 लागू

गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को
10 वर्ष तक का कारावास व एक लाख रुपये तक का जुर्माना

और जल्द ही हिसार में खुलेगा
'इन्डो इज़राईली उत्कृष्टता केन्द्र'

दूध-दही का खाणा-म्हारा देस हरियाणा

- कुरुक्षेत्र स्थित वीटा मिल्क प्लांट देसी गायों के दूध के प्रसंस्करण के लिए समर्पित।
- 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना' के अन्तर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को अप्रैल से सितम्बर तक दिया जाने वाला अनुदान बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया।
- दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनकी बेटी की शादी पर 1100 रुपये राशि की कन्यादान योजना शुरू।
- दुग्ध उत्पादकों के बच्चों के लिए दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में 80 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त करने पर क्रमशः एकमुश्त राशि 2100 रुपये एवं 5100 रुपये की छात्रवृत्ति योजना शुरू।
- हरियाणा डेयरी/दुग्ध संघों द्वारा मिल्क प्लांट, कुरुक्षेत्र में दूध को इकट्ठा करने, प्रोसैस करने और दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन आरम्भ।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.vitaindia.org.in
2. दूरभाषः– 0172–2586826

हरियाणा देश का पहला राज्य
देशी गाय का पास्चुरीकृत 'ए–2'
दूध वीटा बूथों पर उपलब्ध

प्रतिदिन प्रति व्यक्ति
878 ग्राम दूध उपलब्धता
हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर

दुग्ध उत्पादकों के लिए
5 लाख रुपये की
दुर्घटना बीमा योजना शुरू

और जल्द ही पशु चिकित्सा
एवं रोग निदान हेतु
मोबाईल प्रयोगशाला खण्ड स्तर पर भी

डिजिटल हरियाणा

- कैशलेस लेन-देन बारे जिला मुख्यालय, उप-मण्डल, तहसील व उप-तहसील स्तर पर पी.ओ.एस. मशीनें लगाई जा रही हैं।
- हरियाणा में स्टेट पोर्टल से सभी विभागों/बोर्डों इत्यादि की वैबसाइट को लिंक किया गया।
- कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थी तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डी.बी.टी. सुविधा शुरू।
- आधार कार्ड बनाने का 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए 375 स्थाई नामांकन केन्द्र स्थापित। अब तक 99.38 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
- स्वर्ण जयंती योजना के तहत सोनीपत जिले के मुरथल गांव में 191 करोड़ रुपये की लागत से 44 एकड़ भूमि पर एक साईंस सिटी स्थापित करने की योजना।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राशन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ई.पी.डी.एस. पोर्टल।
- सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में ई-दिशा के माध्यम से नई रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू।
- आई.टी. युक्त "ग्राम सचिवालय" योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019 तक 2294 ग्राम सचिवालय बनाने का प्रस्ताव, जिसमें से 1501 ग्राम सचिवालय स्थापित।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.haryanait.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2704922

सेवा का अधिकार अधिनियम-2014

195 सेवाएं अधिसूचित

प्रदेश में

246 ई-सेवाएं शुरू

3616 सांझा सेवा केन्द्र शुरू

5260 गांवों में ऑप्टीकल फाइबर केबल का कार्य पूर्ण

'ई-भूमि' पोर्टल

जमीन की ऑनलाइन खरीद-फरोख्त

ई-स्टॉम्प प्रणाली लागू

सूचना प्रौद्योगिकी से हरियाणा की नई पहचान

- ई-शासन में जी.आई.एस.टैक्नोलोजी के अनूठे उपयोग के लिए जिला प्रशासन गुरुग्राम की जी-त्रिकोणीय परियोजना के लिए जनवरी-2017 में ''नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड-गोल्ड आर्डर''।
- नवजात शिशुओं के जन्म के समय ही आधार पंजीकरण के लिए ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड'' तथा ''फर्स्ट स्टेट आफ इंडिया अवार्ड''।
- ई-टूरिज़्म पर्यटन सुविधाओं की ऑनलाइन बुकिंग के लिए ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- सी.एम. विंडो के माध्यम से जन शिकायतों के निवारण के लिए ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड'' तथा ''स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड''।
- डीलर्स प्रबन्धन के लिए ई-एप्लीकेशन, रिटर्नस की ई-फाईलिंग, सी-फार्म इत्यादि के लिए ''स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड'' व ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- 'थारी पेंशन-थारे पास योजना' के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण के लिए सितम्बर, 2016 को ''स्मार्ट गवर्नेंस गोल्ड अवार्डस'' व ''स्कॉच ऑर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.haryanait.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2704922

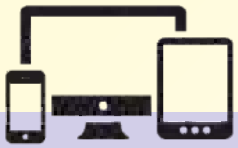

कैशलैस लेन-देन की पहल करने के लिए

डिज़िटल इंडिया अवार्ड

श्रेष्ठ उन्नत राज्य के लिए

ई-गवर्नेंस अवार्ड'

हरियाणा में ई-शासन हेतु

'एक्सिलेंस ऑफ सी.एस.आई. नीहिलेंट' अवार्ड

'स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत' बना जन-जन का अभियान

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत भारत को वर्ष 2019 तक पूर्णतया स्वच्छ बनाने का लक्ष्य।
- प्रदेश के 10 शहरी स्थानीय निकाय खुले में शौच से मुक्त।
- ग्राम पंचायतों में ठोस व तरल कूड़ा-कचरा प्रबन्धन परियोजनाएँ प्रगति पर।
- गांवों में कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय पहली नवम्बर, 2016 से 8100 रुपये मासिक से बढ़ाकर 10,000 रुपये मासिक किया गया।
- अब तक 40 मल शोधन संयंत्र शुरू तथा 26 मल शोधन संयंत्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.harpanchayats.gov.in
2. दूरभाष:– 0172–2654725

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रदेश के सभी गांव
खुले में शौच से मुक्त

और जल्द ही प्रदेश के सभी शहर
भी होंगे खुले में शौच से मुक्त

'स्वर्ण जयन्ती स्वच्छता पुरस्कार योजना'
ग्राम पंचायत को
एक लाख रुपये तथा
जिला स्तर पर
10,000 रुपये
का पुरस्कार

गांवों का 'स्मार्ट' विकास

- माननीय राष्ट्रपति ने प्रदेश के पांच गांवों-गुरुग्राम जिले के अलीपुर, दौलह, हरचन्दपुर व ताजनगर तथा मेवात जिले का रोजकामेव को 'स्मार्ट गांव' बनाने हेतु गोद लिया।
- 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों के लिए 'स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना' शुरू।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा 'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना' के तहत 316 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' के तहत ज़िला पलवल तथा फरीदाबाद के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले 12 गांवों को 20 लाख रुपये प्रति गांव दिए।
- 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के सभी सांसदों ने 15 गांव तथा दूसरे चरण में प्रदेश के 9 सांसदों ने 9 ग्राम पंचायतों को गोद लिया।
- 'विधायक आदर्श ग्राम योजना' के तहत 63 विधायकों द्वारा गांव गोद लिये।
- प्रदेश के 119 गांवों में 'वाई-फाई' की सुविधा शुरू।

और जानकारी के लिए देखें
1. www.harpanchayats.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2654725

प्रदेश के इतिहास में पहली बार
पढ़ी-लिखी पंचायतें
महिलाओं एवं युवाओं को
मिला व्यापक प्रतिनिधित्व

दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
3000-10,000 तक की आबादी वाले
1500 गांवों के विकास पर
5000 करोड़ रुपये होंगे खर्च

और जल्द ही
प्रदेश के सभी गांवों में होगी
वाई-फाई सुविधा

नैतिक स्कूली शिक्षा, मजबूत आधार

- देश के इतिहास में पहली बार शिक्षा शास्त्रियों, अध्यापकों, बुद्धिजीवियों, गणमान्य व्यक्तियों, विद्यार्थियों, गैर-सरकारी संगठनों व आम जनता से सुझाव मांगकर और गहन विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति तैयार।
- नेशनल डिज़िटल साक्षरता परियोजना के अन्तर्गत 1,48,203 लाभार्थियों को ई-साक्षर बनाने हेतु नामांकित किया।
- सभी स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिये अलग-अलग शौचालय बनाये।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.schooleducationharyana.gov.in
2. दूरभाषः— 0172—2562029

990 राजकीय
उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में
14 व्यावसायिक ट्रेड्स शुरू

3200 प्राथमिक पाठशालाओं में
रैमेडियल टीचिंग शुरू

और जल्द ही
प्रत्येक स्कूल में
योग कक्षाएं होंगी शुरू

बेहतर उच्चतर शिक्षा से उज्ज्वल भविष्य की ओर

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के तहत 'स्टार्ट अप' कार्यक्रम आरम्भ करने का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा।
- पी.डी.एम. विश्वविद्यालय, बहादुरगढ़ व स्टार एक्स विश्वविद्यालय, गुरुग्राम में स्थापित।
- वर्ष 2016-17 में 9 स्वःवित्त पोषित डिग्री कॉलेजों में 20 नये कोर्स, 4 में सीटें बढ़ाने तथा 29 अराजकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में 69 नये कोर्स और 5 की सीटें बढ़ाने की तथा वर्ष 2017-18 के लिए 63 नये कोर्स और 4 सीटें बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई।
- 18 नये राजकीय महाविद्यालयों के भवन तथा तीन राजकीय महाविद्यालयों के अतिरिक्त भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू।
- 32 नये स्वःवित्त पोषित डिग्री कॉलेज तथा चार वित्त पोषित लॉ कॉलेज खोलने की मंजूरी।
- ANO's को विभिन्न कैम्पों के लिए Messing Allowance 80 रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।
- ANO's को PRCN, Refresher Course, Training Course हेतु Messing Allowance 65 रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 213 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.highereduhry.com
2. दूरभाषः– 0172–2560246

5 नए राजकीय महाविद्यालय खोले

भूना (फतेहाबाद), खेड़ी गुजरान (फरीदाबाद)
महिला महाविद्यालय पुन्हाना (मेवात)
अटेली (महेन्द्रगढ़) तथा सिरसा

सभी 110 राजकीय महाविद्यालयों में
निःशुल्क
'वाई-फाई' सुविधा शुरू

और जल्द ही हर 20 किलोमीटर पर
एक महिला कॉलेज

युवाओं का कौशल विकास

- वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की एकीकृत कौशल विकास योजना के तहत 8458 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- वर्तमान में अम्बाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, भिवानी, पानीपत और फरीदाबाद के प्रशिक्षण केन्द्रों में लगभग 3500 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूर्ण तथा 4000 से ज्यादा छात्र कौशल प्रशिक्षण ले रहे हैं।
- दुधोला (पलवल) में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय शुरू।
- सात नये राजकीय बहुतकनीकी, नीमका (फरीदाबाद), शेरगढ़ (कैथल), इंद्री (नूंह), मालब (नूंह), छप्पार (चरखी दादरी), जमालपुर शेखां (फतेहाबाद) तथा मन्डकोला (पलवल) में निर्माण कार्य पूर्ण।
- 6 नये राजकीय तथा 124 नये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू।
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 16 नये व्यवसाय कोर्स, 835 नई ट्रेड यूनिटें तथा 13,360 अतिरिक्त सीटें जारी।
- आई.आई.टी., दिल्ली का विस्तार परिसर बाढ़सा (झज्जर) में स्थापित किया जा रहा है।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.itiharyana.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2583249

हरियाणा कौशल विकास मिशन

'सूर्य' (युवाओं की स्किलिंग, अप-स्किलिंग, रि-स्किलिंग व असेस्मेंट)

'दक्ष' (हरियाणा में अनुप्रयुक्त ज्ञान व कौशल का प्रसार) योजनाएं क्रियान्वित

प्रदेश में तकनीकी संस्थानों की स्थापना

कुरुक्षेत्र में

उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान शुरु तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, (NIELIT)

करनाल में केन्द्रीय प्लास्टिक सैटेलाइट केन्द्र

पंचकूला में

राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलोजी संस्थान (NIFT)

और जल्द ही सोनीपत में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की होगी स्थापना।

हरा-भरा म्हारा हरियाणा

- मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हर्बल प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- शिवालिक तथा अरावली की पहाड़ियों में जल एवं मृदा संरक्षण हेतु जल संचयन बांधों का निर्माण।
- जैविक स्त्रोतों के संरक्षण के लिए राज्य में जैव विविधता बोर्ड का गठन।
- स्थानीय लोगों को वन एवं पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने हेतु 2200 स्वयं सहायता समूहों तथा 2487 ग्राम वन समितियों का गठन।

वन्य प्राणियों का संरक्षण

- गिद्ध संरक्षण एवं संवर्धन केन्द्र, पिंजौर से गिद्धों को पहली बार उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया।
- राज्य में चीते की जनगणना हेतु कैमरा ट्रैप सिस्टम लागू।
- कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में इस सिस्टम के तहत 23 चीते पाये गये।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.haryanaforest.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2563988

हर घर हरियाली अभियान

कलमी फलदार पौधे लगाए

पीपली 'जू' का आधुनिकीकरण पूर्ण,
रोहतक 'जू' का आधुनिकीकरण शुरू

और जल्द ही
प्रदेश में बनेंगे 'City Forest'

स्वच्छ जल-सबका अधिकार

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 6 शहरों (सोहना, नूंह, पटौदी, हेली मंडी, फारूखनगर व हथीन) में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज तथा बरसाती पानी की निकासी की सुविधाएं उपलब्ध करवाने व इनके सुधार के लिए 297.20 करोड़ रुपये की परियोजनाएं।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1468 नलकूप तथा 365 बूस्टिंग स्टेशन शुरू।
- शहरी क्षेत्रों की अनाधिकृत कालोनियों में पब्लिक स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जलापूर्ति करने तथा रिवर्स ओसमोसिस (आर.ओ.) संयंत्र स्थापित करने की एक पायलट परियोजना प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत सोनीपत और पानीपत शहरों में सीवरेज़ सुविधाओं के संवर्धन और सुधार के लिए 88.36 करोड़ रुपये तथा सीवरेज उपचार संयंत्रों के निर्माण के लिए 129.51 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर।

बिजली आपूर्ति में सुधार एवं बढ़ोतरी

- जिला पंचकूला के ग्रामीण क्षेत्रों में पहली जनवरी, 2017 से 11 फीडरों से जुड़े हुए 119 गांवों को 24 घण्टे बिजली आपूर्ति हो रही है।
- विभिन्न शहरी क्षेत्रों में भी बिजली सप्लाई प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, गुरुग्राम में स्मार्ट इलैक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित करने का निर्णय।
- विभिन्न क्षमताओं के 92 नए सब-स्टेशनों की स्थापना तथा

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.wss.hry.nic.in
2. दूरभाषः– 0172–2561672

643 गांवों में पेयजल सुविधा में
सुधार एवं बढ़ोतरी

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में
171 नहर आधारित व 45 नलकूप
आधारित जलघर स्थापित

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में
6236 किलोमीटर लम्बी
पाइप लाईनें बिछाईं

325 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई।

- 4490 एम.वी.ए. की अतिरिक्त प्रसारण क्षमता तथा 768 किलोमीटर की प्रसारण लाईनें जोड़ी गईं।
- 5665 किलोमीटर लम्बी नई लाईनें बिछाई तथा 55,936 नये ट्रांसफामर लगाए गए।
- यमुनानगर में 800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल यूनिट 3 के लिए 102 मिलियन टन कोयले के भंडार सहित कल्याणपुर-बादलपारा कोल ब्लॉक एच.पी.जी.सी.एल. का आवंटन।
- आगामी 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 तक) में प्रसारण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए 77 नए सब-स्टेशन बनाने, 347 वर्तमान सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि करने तथा 1730 किलोमीटर लम्बी प्रसारण लाईनें जोड़ने की योजना बनाई।
- बिजली आपूर्ति प्रणाली में सुधार लाने तथा बिजली चोरी रोकने के लिए फीडर सैनीटेशन प्रोग्राम शुरू।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.hvpn.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2560579

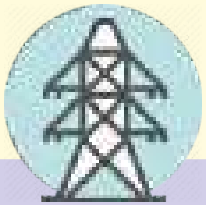

म्हारा गांव–जगमग गांव

264 फीडरों (लगभग 726 गांव) में 15 घंटे तक
33 फीडरों (लगभग 105 गांव) में 18 घंटों तक
32 फीडरों (127 गांव) में 24 घंटों तक

बिजली आपूर्ति बढ़ाई

बिजली बिल जुर्माना माफी योजना

लगभग 1,52,494 घरेलू एवं गैर-घरेलू
उपभोक्ता जनवरी, 2017 तक
हुए लाभान्वित

और जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना

(316 करोड़ रुपये स्वीकृत)

सौर ऊर्जा-बेहतर विकल्प

- हरियाणा ग्लोबल सम्मिट-2016 में हरियाणा सोलर पावर पॉलिसी-2016 के तहत 44 निवेशकों ने राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 96,213 करोड़ रुपये के निवेश के लिये सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर।
- 500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्थापित करने के लिए सौर ऊर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे.वाई.) का गठन।
- हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष में स्वच्छ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा पानीपत थर्मल पॉवर स्टेशन में 10 मेगावाट पानीपत सोलर पॉवर प्रोजेक्ट चालू।
- विभिन्न जिलों में 441.06 लाख रुपये की लागत से 69 ऑफ ग्रिड सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित।
- एक लाख सौर प्रकाश प्रणालियां (मनोहर ज्योति) नामक नई परियोजना।
- ऑफ ग्रिड बायोमास बगैर गैस आधारित संयंत्रों की सर्वोच्च अतिरिक्त क्षमता के लिए हरियाणा को प्रथम पुरस्कार मिला।
- सभी नागरिकों को सब्सिडी दरों पर एल.ई.डी. बल्ब दिए जा रहे हैं।
- 11 जिलों के 22 अनुसूचित जाति के गांवों में 480.15 लाख रुपये की लागत से 160 किलोवाट क्षमता की 1120 सौर पथ प्रकाश प्रणालियां लगाई गईं।
- 12 मेगावाट के धरातल आधारित सोलर पावर प्लांट लगाए।

और जानकारी के लिए देखें

1. www.hareda.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2585733

गुरुग्राम में 121 देशों के
संगठन के इन्टरनेशनल सोलर एलायंस
(आई.एस.ए.)
का वैश्विक सचिवालय निर्माणाधीन

छतों के ऊपर
सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए
हरियाणा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

स्वर्ण जयंती वर्ष में किसानों को
3050 सोलर पम्प देने के लिए
45.89 करोड़ रुपये की योजना शुरू

Shri Manohar Lal Khattar

PATANJALI

NCC
NCC

उद्योगों का हो रहा तीव्र विकास

- नई उद्योग नीति का लक्ष्य राज्य में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 8 प्रतिशत से अधिक करना, चार लाख से अधिक रोजगार सृजित करना और एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना है।
- 'जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट' विनिर्माण पद्धतियों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया।
- 10 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमोदनों/स्वीकृतियों तथा एक एकड़ से अधिक की भूमि परियोजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थित हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा तथा 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं तथा एक एकड़ से कम की भूमि परियोजनाओं की स्वीकृति जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दी जा रही है।
- अनुसूचित जाति के लोगों व महिलाओं को रोजगार देने पर प्रतिवर्ष 36 हजार रुपये तथा सामान्य श्रेणी के लोगों को रोजगार देने पर प्रति वर्ष 30 हजार रुपये की रोजगार सृजन सब्सिडी पांच साल तक देने का प्रावधान।
- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति तथा 'मेक इन इण्डिया' पहल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सैकेण्डरी सेक्टर के योगदान को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया गया।
- उद्यमियों को एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए E-biz Portal शुरु।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.haryanaindustries.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2701344

नई उद्योग नीति के चार प्रमुख स्तम्भ

निर्बाध (NIRBADH) (New Industrial Regulation by Automatic Approvals and Delegation in Haryana), फाईन (Financial Incentives and No Enhancements) विस्तार (VISTAR) (Vat, Interest Stamp Duty, Audit Assistance and Rating) तथा प्रणेता (PRENTA) (Professional and New Entrepreneurs Tax Assistance)

हरियाणा में देश के कुल उत्पादन का

80 प्रतिशत एक्सीलेटर, 52 प्रतिशत क्रेन्स, 50 प्रतिशत कारें और 33 प्रतिशत टू-व्हीलर्स के निर्माण में योगदान

कुल 15,482 सूक्ष्म व लघु उद्योग
335 मध्यम व बड़े उद्योग स्थापित
जिनमें 19,444 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश
1,96,831 लोगों को रोजगार मिला

विदेशी निवेश आकर्षित

- अमेरिका व कनाडा दौरे के परिणामस्वरूप अनुमानित 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश तथा प्रदेश के 40 हजार लोगों के लिए रोज़गार के नए अवसर सृजित होने की संभावना।
- गुरुग्राम में 'हैपनिंग हरियाणा' ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट के आयोजन से 359 एम.ओ.यू. साईन हुए, जिनसे प्रदेश में 5.84 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा 5 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है।
- गुरुग्राम में हरियाणा अप्रवासी दिवस-2017 के दौरान कुल 24 एम.ओ.यू. हुये, जिनके क्रियान्वित होने से प्रदेश में 20,430 करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा 45 हजार से अधिक लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है।
- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने चीन एवं जापान दौरे के दौरान बीजिंग (चीन) में सम्भावी निवेशकों के साथ आठ समझौते किये।
- गुरुग्राम में आयोजित सम्मिट में 12 देशों चीन, चेक गणराज्य, जापान, मॉरीशस, मलावी, न्यूजीलैंड, पेरू, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ट्यूनीशिया, यू.के. और कनाडा के ओंटारिया प्रान्त ने भाग लिया।
- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिंगापुर व हांगकांग यात्रा के दौरान 18,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए पांच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए।

और जानकारी के लिए देखें

1. www.hsiidc.org.in
2. दूरभाषः– 0172–2590324

अमेरिका व कनाडा दौरा (पांच महत्वपूर्ण समझौते)
यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन (United Technologies Corporation), **एलगोनक्वीन कॉलेज** (Algonquin College), **अप्लाईड मैटीरियल** (Applied Material), **गूगल** (Google) (डिज़िटल साक्षरता हेतु) तथा **सिस्को** (CISCO)

सम्मिट के दौरान हुए 359 एम.ओ.यू.

निवेश क्षेत्र	एम.ओ.यू की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)	प्रस्तावित रोजगार
रक्षा एवं एयरोस्पेस	2	2170	10000
शिक्षा एवं कौशल विकास	11	976.25	3170
निर्माण क्षेत्र	112	8229.49	37718
रियल एस्टेट	23	105850.38	118502
आधारभूत संरचना	13	286925	122900
एग्रो खाद्य प्रसंस्करण तथा सम्बद्ध उद्योग	49	18457.48	21541
इलैक्ट्रोनिक, आई.टी., आई.टीज.	37	9839.36	106805
फार्मास्यूटिकल एवं रसायन उद्योग	8	1822.54	1603
ऑटो, ऑटो कम्पोनेट्स एण्ड लाईट इंजीनियरिंग	16	1267.5	7236
टैक्सटाईल/अपैरल/बुनाई-कढ़ाई/टैक्निकल टैक्सटाईल	17	463.89	6702
फुटवियर एण्ड एसैस्रीज	9	241.73	1622
ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा तथा सोलर पार्क	41	122112.5	51705
निवेश प्रोत्साहन समर्थन	21	25926.5	12649
कुल निवेश	359	584282.62	502153

व्यापारियों के लिए ई-सेवायें एवं राहतें

- शराब के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए आबकारी लाइसेंसधारियों के लिए ई-परमिट एवं ई-पास प्रणाली शुरू।
- जूता उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 500 रुपये और इससे अधिक के एम.आर.पी. वाले जूतों पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और जूतों के ऊपर के हिस्से को वैट से छूट।
- कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में निर्मित खल, बिनौला, बेसन तथा सूती धागे को कर से छूट।
- इलैक्ट्रिकल वाहनों की बिक्री पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की।
- राज्य के कृषि उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 'सेवियां' पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत।
- परिवारों को राहत प्रदान करने और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए रसोई में पत्तेदार सब्जियों को काटने वाला 'छोटा टोका' पर कर अदायगी से छूट।
- एल.ई.डी. लाईटों, पाइप फिटिंग एवं प्री. फेब स्टील स्ट्रक्चर पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत।
- मेहंदी पर वैट की दर 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य।
- बायो डीजल पर लगने वाला 12.5 प्रतिशत वैट समाप्त।
- रॉयल्टी एवं करों के संग्रहण को सरल बनाने और कर चोरी कम करने के लिए विभाग द्वारा यमुनानगर में 'ई-रवाना' योजना शुरू।
- आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रभावित पंजीकृत डीलरों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कर, ब्याज, जुर्माना और अन्य देय राशि से राहत देने के लिए 'आम राहत' योजना बनाई।

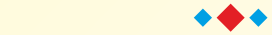

और जानकारी के लिए देखें

1. www.haryanatax.com
2. दूरभाषः– 0172–2590990

पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए
बड़ी खनन इकाइयों/ब्लॉकों के ठेके देने की बजाय
छोटी खनन इकाइयों/ब्लॉकों को
ठेके पर दिये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय

ई–पंजीकरण
ई–अदायगी, ई–फायलिंग,
ई–निविदा, ई–रिफंड व सी–फार्म
की **ऑनलाईन सुविधा**

व्यापारियों को प्रोत्साहित करने हेतु
'अपना बिल अपना विकास'
पुरस्कार योजना शुरू

हरियाणा परिवहन-शान की सवारी

- सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के सुधार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन से टिकट जारी करने, आर.एफ.आई.डी. पास देने तथा बसों में जी.पी.एस. प्रणाली की स्थापना करने जैसे अनेक नये कदम उठाए गए।
- गांव छपेड़ा (मेवात) और गांव बहीन (पलवल) में चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
- हरियाणा राज्य परिवहन के कर्मचारियों का वर्दी भत्ता 1000 रुपये से बढ़ाकर गर्मियों के लिए 1350 रुपये प्रतिवर्ष तथा सर्दियों के लिए 1450 रुपये प्रति तीन वर्ष किया गया।
- आपातकाल के पीड़ित (पति-पत्नी दोनों) को हरियाणा परिवहन की सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा तथा वोल्वो बसों के किराए में 75 प्रतिशत की छूट।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.hartrans.gov.in
2 दूरभाषः– 0172–2727263

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति की तर्ज़ पर
नई राज्य सड़क सुरक्षा नीति-2016

बस बेड़े में 484 नई बसें शामिल
600 नई बसें शामिल
करने की स्वीकृति

और जल्द ही प्रदेश के
सभी बस अड्डों पर लगेंगे
सी.सी.टी.वी. कैमरे

एक्सप्रेस-वे एवं सड़कों का बिछा जाल

- 135 किलोमीटर लम्बे छः लेन कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे, 136 किलोमीटर लम्बे कुण्डली गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे तथा दिल्ली के मुकरबा चौक से पानीपत तक 70 किलोमीटर एन.एच.-1 को 8 लेन करने की प्रक्रिया शुरू।
- 135.65 किलोमीटर लम्बे इस एक्सप्रेस-वे के 52.33 किलोमीटर लम्बे मानेसर-पलवल खण्ड पर यातायात शुरू।
- 505 किलोमीटर लम्बे 4 नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित।
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, मरम्मत और सुधार पर 3563 करोड़ रुपये की राशि खर्च।
- 14 आर.ओ.बी.,12 आर.यू.बी. पर 572 करोड़ रुपये खर्च तथा 25 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का कार्य प्रगति पर।
- हरियाणा राज्य सड़क विकास निगम द्वारा प्रदेश के एन.सी.आर. में सड़क और पुलों के निर्माण कार्यों पर 419 करोड़ रुपये की राशि खर्च।
- पहली बार सड़क निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी अपनाई गई, जिसके आधार पर हांसी में परीक्षण के तौर पर 5 कि.मी. लम्बी सड़क को आवंटित किया।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.haryanapwd.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2618101

दशकों से अधूरे पड़े
कुण्डली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी.)
एक्सप्रेस-वे का निर्माण
2320 करोड़ रुपये
की लागत से कार्य दोबारा शुरू

485 किलोमीटर लम्बे
राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार,
8720 किलोमीटर लम्बी
सड़कों का सुधार

प्रदेश में 11 टोल टैक्स
बैरियर हटाए

आधुनिक एवं सुगम मैट्रो, रेल एवं हवाई सेवायें

- ट्राई सिटी में मैट्रो परियोजना के लिए यू.टी. प्रशासन, हरियाणा सरकार व पंजाब सरकार के बीच हुआ समझौता।
- सोनीपत के गुण्डली से नरेला तक दिल्ली मैट्रो के विस्तार को मंजूरी।
- गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से सोहना रोड़ तक दिल्ली मैट्रो के विस्तार की योजना।
- फरीदाबाद के वाई.एम.सी.ए. चौक से बल्लभगढ़ तक मैट्रो विस्तार का कार्य शुरू।
- दिल्ली मैट्रो का बहादुरगढ़ तक विस्तार करने का कार्य प्रगति पर, जबकि गुरुग्राम और फरीदाबाद को भी मैट्रो से जोड़ने की योजना।
- 740 करोड़ रुपये की लागत से 81 किलोमीटर लम्बी सोनीपत-जींद रेलवे लाइन जनता को समर्पित।
- रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन करने के लिए रेलवे के साथ एम.ओ.यू. किया जा रहा है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का गठन।
- मथुरा-पलवल चौथी लाइन-80 किलोमीटर, बाईपास अम्बाला मोहड़ी शम्भू 7 किलोमीटर तथा रोहतक-भिवानी 48 किलोमीटर के लिए 1074 करोड़ रुपये की तीन नई रेल परियोजनायें स्वीकृत।
- हिसार एयरोड्रोम को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडड़ा, रख-रखाव, मरम्मत, ओवरआल हब तथा समेकित विमानन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.haraviation.gov.in
2. दूरभाषः— 0172—2709386

फरीदाबाद में 2494 करोड़ रुपये की लागत से 13.87 किलोमीटर लम्बी बदरपुर-मुजेसर मैट्रो रेल सेवा आरंभ

देश की पहली सी.एन.जी. आधारित डी.ई.एम.यू. रेल सेवा रेवाड़ी से रोहतक के बीच शुरू

और जल्द ही कुरुक्षेत्र व करनाल के बीच बनेगा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

निरोगी काया, स्वस्थ जीवन का आधार

- छः जिला अस्पतालों तथा तीन चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.पी.पी. मोड पर एम.आर.आई. और सी.टी. स्कैन मशीनें स्थापित।
- हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें परिवार नियोजन के उपलब्ध साधनों में गर्भनिरोधक टीके को सर्वप्रथम शामिल किया गया।
- शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 36 हुई।
- पी.एन.डी.टी. एक्ट का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मार्च 2017 तक 213 एफ.आई.आर. तथा एम.टी.पी एक्ट का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 214 एफ.आई.आर. दर्ज।
- प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर अप्रैल, 2017 में बढ़कर 926 हुई।
- डेंगू निदान एवं रोकथाम के लिए सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त उपचार सुविधा तथा बी.पी.एल. परिवारों के लिए प्लेटलेट्स मुफ्त उपलब्ध।
- तम्बाकू-युक्त सामग्री, गुटका और पान-मसाला पर प्रतिबन्ध।
- विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का रोगियों को लाभ देने के लिए पी.जी.आई., रोहतक में 'मरीज मित्र' योजना पायलट आधार पर शुरू।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.haryanahealth.nic.in
2. दूरभाषः– 0172–2584549

'मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना'

सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में द्वितीय स्तरीय सर्जरियां, 73 मूलभूत प्रयोगशाला जांच, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ई.सी.जी., मुफ्त रेफरल परिवहन, इन्डोर उपचार सेवाएं, 21 दंत चिकित्सा प्रक्रियाएं एवं 231 विभिन्न प्रकार के आप्रेशन **निःशुल्क**

सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाईयां मुफ्त

'मिशन इन्द्रधनुष'

वर्ष 2020 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का **सम्पूर्ण टीकाकरण करने का लक्ष्य**

चिकित्सा शिक्षा का हब बना हरियाणा

- अमेरिका की एन.सी.आई. की तर्ज़ पर बाढ़सा, जिला झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बनेगा।
- भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां में डायलिसिस मशीन और केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित।
- शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ में टी.बी. के प्रति मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए एक सी.बी.एन.ए.ए.टी. मशीन स्थापित।
- ई.एस.आई. डिस्पेंसरियों तथा अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ का वर्दी धुलाई भत्ता 700 रुपये से बढ़ा कर 1150 रुपये मासिक किया।
- बरवाला (पंचकूला), साहा (अम्बाला) व खरखौदा (सोनीपत) में मोबाईल डिस्पेंसरी खोली जाएंगी।
- पण्डित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक में एंडोस्कॉपी हैल्पलाइन स्थापित।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.dmerharyana.org.in
2. दूरभाषः– 0172–2583905

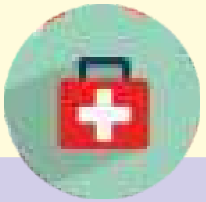

हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य

और जल्द ही कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी

कुटैल (करनाल) में एम.बी.बी.एस., एम.डी., एम.डी.एस., पैरा मेडिकल और नर्सिंग के पोस्ट ग्रेजुएट तक के पाठ्यक्रम शामिल होंगे

हर जन का सपना-बने घर अपना

- 'दीनदयाल जन आवास योजना' के तहत अवैध कालोनियों पर अंकुश लगेगा।
- विभिन्न स्थानों पर 10,326 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर, जिनमें 7,138 मकान बी.पी.एल. परिवारों के लिए हैं।
- विभिन्न स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 882 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से बनने वाले 11,259 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स के निर्माण की मंजूरी।
- गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य वर्ग के लिए बनने वाले फ्लैट्स के निर्माण कार्य पर 483.16 करोड़ रुपये खर्च।
- 'ट्रांजिट ऑरिएंटिड' नीति घोषित, जिसमें जनसंख्या की सघनता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मैट्रो मार्गों के साथ-साथ उन्नत बुनियादी ढांचा विकसित करने का प्रावधान है।
- हरियाणा बिल्डिंग कोड 2016, पहली जुलाई, 2016 से लागू।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.hbh.nic.in
2. दूरभाषः– 0172–2568006

मिशन सभी के लिए घर–2022

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शहरी गरीबों के आवासीय ऋणों पर ब्याज दरों में 6.5 प्रतिशत रियायत

'दीनदयाल जन आवास योजना'

निम्न तथा मध्यम क्षमता वाले शहरों में सस्ती प्लॉटिड आवासीय कालोनी की स्थापना

14,786 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण

जिनमें 14,420 फ्लैट्स

बी.पी.एल. परिवारों के लिए

अंत्योदय दर्शन:गरीबों का कल्याण

- 'लाडली पेंशन' योजना के तहत 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के माता/पिता, जिनकी सन्तान केवल लड़की/लड़कियां हैं और वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो, को 1600 रुपये मासिक भत्ता सुविधा।
- हरियाणा ऐसा पहला प्रमुख राज्य बन गया है, जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से शत-प्रतिशत पेंशन लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है।
- निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत बच्चे के माता-पिता/संरक्षक, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो, को बच्चे की 21 वर्ष आयु पूर्ण होने तक 700 रुपये की वित्तीय सहायता।
- 18 वर्ष तक के स्कूल न जा सकने वाले निःशक्त बच्चों की वित्तीय सहायता 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमास की।
- 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' के तहत लगभग 57 लाख बैंक खाते खोले गये।
- 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के तहत 25 लाख से अधिक लोग पंजीकृत।
- 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' के तहत 7,95,662 लोग पंजीकृत।
- वृद्धावस्था में आय सुनिश्चित करने व असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए 'अटल पेंशन योजना' के तहत 1000 रुपये से 5000 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित।

◆◆◆

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.scbchry.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2721874

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता,
विधवा एवं बेसहारा महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन,
बौना भत्ता, किन्नर भत्ता की राशि
पहली नवम्बर, 2016 से
बढ़ाकर 1600 रुपये मासिक
जिसमें प्रतिवर्ष 200 रुपये की बढ़ोतरी

हरियाणा पहली अप्रैल, 2017 से
कैरोसिन मुक्त

'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना'
लगभग 3 लाख गरीब परिवारों को
गैस कनैक्शन दिये

बेटियों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण के अनूठे प्रयास

- 'आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना' के तहत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये, सभी परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये तथा अब परिवार में जन्मी तीसरी बेटी को भी दूसरी बेटी की तर्ज पर मिलेगा लाभ।
- हर जिला मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना व उप-मण्डल स्तर पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित।
- महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार, लाईफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, विशिष्ट उपलब्धियों पर खेल पुरस्कार, सरकारी व सामाजिक सेवा पुरस्कार आदि दिये जाते हैं।
- सरकार का लक्ष्य International Health Expert के मानदण्डों के अनुसार लिंगानुपात 950 तक करने का है।
- ''सुकन्या समृद्धि खाता योजना'' के अन्तर्गत बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकता है।
- हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए करनाल, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, हिसार व नारनौल में 'वन स्टॉप' सैंटर सखी स्थापित।
- छात्राओं की स्नातक स्तर तक राजकीय महाविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में ट्यूशन फीस माफ।
- छात्राओं के लिए 123 मार्गों पर बस सेवा आरम्भ।
- गांव हसनपुर, जिला सोनीपत में 'नन्दघर' नाम से देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केन्द्र शुरू।

और जानकारी के लिए देखें

1. www.wcdhry.gov.in
2. दूरभाषः— 0172—2560349

जिला मुख्यालय पर महिला पुलिस थानों की सूची

जिला	इन्चार्ज का नाम	सम्पर्क हेतु दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर	
पंचकूला	सुश्री मंजीत	8146630022	(0172)-2021091
अम्बाला	सुश्री रजनी	9729990165	(0171)-2551091
कुरुक्षेत्र	सुश्री प्रवीन	7056700135	(01744)-221091
करनाल	सुश्री पवन	8572881091, 8295322680	(0184)-2251091
पानीपत	सुश्री कविता	7056731091	(0180)-2691091
सोनीपत	सुश्री कविता	8053882349	(0130)-2241091
सोनीपत (खानपुर कलां)	सुश्री कमलेश	8059882350	(01263)-283100
रोहतक	सुश्री गरिमा देवी	8199001091, 8222055455	(01262)-271091
झज्जर	सुश्री सुदेश	8930111091	(01251)252061
रेवाड़ी	सुश्री सरोज बाला	7056666133	(01274)-251722
गुरुग्राम	सुश्री कैलाश	9212283922	(0124)2218057
फरीदाबाद	सुश्री सुशीला	9582200061, 9891279220	(0129)-2261092
यमुनानगर	सुश्री कुलबीर कौर	8818001307, 9416202825	(01732)-251002
नूंह	सुश्री राज कलां	8397991091, 8683996541	7027881091
पलवल	सुश्री कमला देवी	8930511091	(01275)-241091
नारनौल	सुश्री नीलम	7056601091	(01282)-251091
भिवानी	सुश्री लक्ष्मी देवी	8814011409, 9729346600	(01664)-251091
सिरसा	सुश्री सीमा सोढी	8813801091	(01666) 231091
फतेहाबाद	सुश्री बिमला	8814011721	(01667)-230140
हिसार	सुश्री सुनीता	8814031091, 7357270290	(01662)-271091
जींद	सुश्री संतोष देवी	8813991091	8814011537
कैथल	सुश्री निर्मला	9053052118	9053052218

सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय:

- सभी वर्ग की विधवाओं, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं तथा अनाथ, बेसहारा बच्चों, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो, की शादी के लिए 41,000 रुपये की शगुन राशि।
- सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिये 11,000 रुपये की शगुन राशि।
- समाज के सभी वर्ग के लोगों जिनके पास ढ़ाई एकड़ कृषि भूमि या एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय है, की लड़की की शादी के लिये 11,000 रुपये शगुन राशि।
- किसी भी जाति एवं आय वर्ग से सम्बन्धित महिला खिलाड़ी को उसकी स्वयं की शादी के लिये 31,000 रुपये की शगुन राशि।
- 'मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना' के तहत हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति के लड़का या लड़की से विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 1,01,000 रुपये की।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतिमास 230 रुपये से 1200 रुपये तक छात्रवृत्ति के साथ-साथ सभी नॉन रिफण्डेबल फीसों की प्रतिपूर्ति की जाती है।
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अदालती मुकद्दमों की पैरवी हेतु कानूनी सहायता उपलब्ध।
- जातीय आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों जैसे भूमि का अनाधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती, बलात्कार, आगजनी तथा नरसंहार से पीड़ितों को अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के अन्तर्गत 85000 रुपये से 8.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.socialjusticehry.gov.in
2. दूरभाष:– 0172–2704212

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

सभी वर्गों की बी.पी.एल. विधवाओं को
उनकी लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये
अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति व
टपरीवास जाति के बी.पी.एल. परिवारों की
लड़कियों की शादी के लिए 41,000 रुपये

डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को
मैट्रिकोत्तर स्तर तक कक्षावार
8000 रुपये से 12,000 रुपये तक छात्रवृत्ति
पिछड़े वर्ग के 10वीं कक्षा के छात्रों को प्रतिशतता के आधार पर प्रोत्साहन राशि

अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं/लड़कियों को स्वरोजगार हेतु सिलाई का एक वर्षीय प्रशिक्षण

कच्चा सामान खरीदने के लिए 300 रुपये एवं 600 रुपये का
मासिक भत्ता तथा एक सिलाई मशीन की भी सुविधा

- अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों को विभिन्न उच्च एवं प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुफ्त प्रशिक्षण।
- 'कौशल विकास योजना' के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के उन बेरोज़गार युवकों को हारट्रोन के जरिये टंकण तथा डाटा एन्ट्री में मुफ्त प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 250 रुपये मासिक वजीफा दिया जाता है।
- गाडी एवं लोहार जाति को टपरीवास जाति की सूची में शामिल कर उन्हें विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
- सफाई तथा जान जोखिम मे लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पहली से 10वीं कक्षा तक के डे-स्कोलर छात्रों के लिए 110 रुपये प्रतिमास छात्रवृत्ति और 750 रुपये तदर्थ वार्षिक अनुदान दिया जाता है।

अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य करने वाली पंचायतों को **50,000 रुपये** की प्रोत्साहन राशि

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पिछड़े वर्ग के छात्रों को 160 रुपये से 750 रुपये तक मासिक छात्रवृत्ति

हरियाणा विमुक्त घुमंतू जाति विकास बोर्ड गठित

खेलों में दम दिखाया, हरियाणा का नाम चमकाया

- रियो ओलम्पिक-2016 में कुश्ती में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी साक्षी मलिक को 2.50 करोड़ रुपये तथा रियो पैरा ओलम्पिक-2016 में शॉटपुट में रजत पदक विजेता दीपा मलिक को 4 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया।
- रियो ओलंपिक-2016 में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, कुश्ती खिलाड़ी कुमारी विनेश फौगाट, अमित कुमार तथा विरेन्द्र सिंह को अर्जुन पुरस्कार तथा महावीर सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया।
- 'पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आल इंडिया नेशनल स्टाईल कबड्डी टूर्नामेंट' में प्रथम विजेता टीम को एक करोड़ रुपये, द्वितीय विजेता टीम को 50 लाख रुपये तथा तृतीय विजेता टीम को 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
- प्रदेश में 371 गोल्डन जुबली खेल नर्सरियां स्थापित।
- पांच-पांच करोड़ रुपये की लागत से प्रत्येक जिले में एक-एक खेल का स्वर्ण जयंती 'सैंटर आफ एक्सीलैंस' बनाने की प्रक्रिया शुरू।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.haryanasports.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2583082

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस पर
'भारत केसरी दंगल' के
प्रथम विजेता को एक करोड़ रुपये
दूसरे विजेता को 50 लाख रुपये
तीसरे विजेता को 25 लाख रुपये

पुरस्कार राशि में अभूतपूर्व बढ़ोतरी				
खेल प्रतियोगिताएं	स्वर्ण पदक विजेता को	रजत पदक विजेता को	कांस्य पदक विजेता को	प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को
ओलम्पिक में	6 करोड़	4 करोड़	2.50 करोड़	15 लाख
एशियन में	3 करोड़	1.50 करोड़	75 लाख	7.50 लाख
कॉमनवेल्थ गेम्स में	1.50 करोड़	75 लाख	50 लाख	7.50 लाख
राष्ट्रीय खेलों में	5 लाख	3 लाख	2 लाख	–
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में	3 लाख	2 लाख	एक लाख	–
राज्य स्तरीय अखाड़ा कुश्ती प्रतियोगिता	5,100	3,100	2,100	–
राज्य स्तरीय कुमार दंगल प्रतियोगिता	51,000	31,000	21,000	–

और जल्द ही प्रत्येक जिले में खुलेंगे
स्वर्ण जयंती खेल सुविधा केन्द्र

पर्यटन क्षेत्र में उभरता हरियाणा

- 'स्वदेश दर्शन योजना' के अन्तर्गत कुरुक्षेत्र शहर के पांच प्रमुख स्थानों में सन्निहित सरोवर, अमीन कुंड, नरकातारी, ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर और कुरुक्षेत्र शामिल किये गये, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 97 करोड़ 34 लाख रुपये की राशि स्वीकृत।
- 'स्वर्ण जयन्ती सिन्धु दर्शन योजना' के तहत 10,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री अधिकतम 50 यात्रियों तक तथा 'मानसरोवर यात्रा योजना' के तहत 50,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री अधिकतम 50 यात्रियों को वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है।

समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

- गांव राखीगढ़ी (हिसार) में एक स्थल संग्रहालय और व्याख्यान केन्द्र की स्थापना की जा रही है।
- पंचकूला में राज्य स्तरीय संग्रहालय की स्थापना की जा रही है।
- सरस्वती नदी के अनुसंधान एवं पुनरोद्धार के लिए सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन।
- अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से यमुनानगर के गांव मुगलवाली में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू।
- केन्द्र सरकार की "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" योजना के तहत अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए तेलंगाना राज्य के साथ एक समझौता।
- गीता जयन्ती उत्सव कुरुक्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा इसके साथ-साथ पहली बार राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया गया।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.haryanatourism.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2704886

'स्वर्ण जयन्ती गुरुदर्शन यात्रा'

राज्य के 50 तीर्थ यात्रियों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये या वास्तविक खर्चे का 50 प्रतिशत प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता

सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार का भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद, नई दिल्ली के साथ एक समझौता

और जल्द ही नारनौल-महेन्द्रगढ़-माधवगढ़-रेवाड़ी विकसित होगा ग्रामीण पर्यटन सर्किट के रूप में

देश के रक्षकों का सम्मान

- आई.ई.डी. बलास्ट के दौरान शहीद होने पर अनुग्रह राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तथा इसे पुनः बढ़ाकर 50 लाख रुपये की।
- युद्ध/आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के लिए अनुग्रह अनुदान निःशक्तता के आधार पर 15 लाख रुपये, 25 लाख रुपये तथा 35 लाख रुपये दी जाती है।
- हरियाणा से सेना में कमीशन पाने वाले अधिकारियों को उनके कुशल प्रशिक्षण के उपरांत एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- सेना मेडल डिसटिंगविस्ड सर्विस/डिवोशन टू ड्यूटी के अवार्डी, जो कि फोर्सिज के हों और जिन्हें यह अवार्ड 31 मार्च, 2008 व 19 फरवरी, 2014 से पहले प्राप्त हुआ हो, को 34,000 रुपये नकद व 3,500 रुपये एन्यूटी दी जाती है तथा जिन्हें यह अवार्ड 19 फरवरी, 2014 के बाद मिला है, उन्हें 1.75 लाख रुपये की एकमुश्त नकद राशि दी जाती है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों तथा विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 4500 रुपये मासिक की।
- राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में पढ़ रहे हरियाणा के छात्रों को दी जाने वाली वार्षिक छात्रवृत्ति की राशि पहली अप्रैल, 2017 से 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र की।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. दूरभाषः– 0172–2560321

युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना एवं अर्द्धसैनिक बल के जवानों की अनुग्रह राशि
20 लाख रुपये से
बढ़ाकर 50 लाख रुपये

युद्ध/आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल सैनिकों को अनुग्रह अनुदान राशि
निःशक्तता के आधार पर
5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 15 लाख रुपये

दिव्यांग, नेत्रहीन, पैराप्लेजिक, टैटराप्लेजिक और हैमियाप्लेजिक भूतपूर्व सैनिकों की आर्थिक सहायता
पहली नवम्बर, 2016 से
3000 रुपये मासिक
जिसमें प्रतिवर्ष पहली नवम्बर से 400 रुपये की वृद्धि

और जल्द ही मातनहेल (झज्जर) में खुलेगा सैनिक स्कूल

रोजगार के नये आयाम

- बेरोजगार युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पायलट परियोजना के रूप में हिसार में एक राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्र की स्थापना।
- बैंकों के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता त्रैमासिक आधार पर।
- बेरोजगारी भत्ता योजना की राशि में पहली नवम्बर, 2016 से 12वीं या इसके समकक्ष स्नातक और इसके समकक्ष व स्नातकोत्तर बेरोजगारों की राशि को क्रमशः 900, 1500 तथा 3000 रुपये मासिक किया।
- "सक्षम युवा योजना" का लाभ उठाने के लिए वैबसाईट www.hreyahs.gov.in पर पंजीकरण किया जा रहा है।
- पहली अप्रैल, 2017 से "सक्षम युवा योजना" में विज्ञान तथा गणित स्नातक प्रार्थियों को शामिल किया।
- यह केन्द्र naukri.com तथा monster.com जैसे निजी क्षेत्रों के सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) सघन मॉडल पर आधारित है।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.hssc.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2586501

सक्षम युवा योजना

स्नातकोत्तर बेरोजगारों को
3000 रुपये प्रतिमाह भत्ता
100 घंटे कार्य करने पर 6000 रुपये प्रतिमाह मानदेय

24,826 युवा बेरोजगारों को
63.76 करोड़ रुपये की राशि
भत्ते के रूप में वितरित

1708 प्रार्थियों का
सरकारी एवं गैर सरकारी
संस्थाओं में समायोजन

श्रमिकों का कल्याण एवं सम्मान

- वेतन मजदूरी संदाय (हरियाणा संशोधन) 2016 पारित, इनमें वेतन अदायगी अधिनियम में संशोधन द्वारा बैंकों के माध्यम से वेतन का भुगतान करने का प्रावधान।
- भवन एवं सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में अपंजीकृत मजदूर की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर दी जाने वाली एक लाख रुपये तक की सहायता राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया।
- अब बिना सरकार की अनुमति के 'ले ऑफ छंटनी' और बंद करने के लिए 100 श्रमिकों के अदारों की सीमा बढ़ाकर 300 श्रमिक तक होगी।
- महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य पर लगाने की छूट।
- श्रमिकों की पत्नियों को दी जाने वाली प्रसूति सहायता को दो बच्चों से बढ़ाकर तीन लड़कियों तक, छात्रवृत्ति योजना का लाभ तीन बच्चों से बढ़ाकर तीन लड़कियों व दो लड़कों तक तथा कन्यादान योजना का लाभ दो लड़कियों से बढ़ाकर तीन लड़कियों की शादी तक किया।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.hrylabour.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2701373

मासिक एवं दैनिक वेतन में 2.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी

श्रमिक वर्ग	रुपये (प्रतिमाह)
अकुशल श्रमिक	8280.20
अर्द्धकुशल 'ए'	8694.20
अर्द्धकुशल 'बी'	9128.91
कुशल श्रमिक 'ए'	9585.35
कुशल श्रमिक 'बी'	10064.62
उच्च कुशल श्रमिक	10567.85

भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों की निःशक्तता मासिक पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये

और जल्द ही पंजीकृत मजदूरों को पहचान पत्र के स्थान पर मिलेंगे स्मार्ट कार्ड

सुदृढ़ पुलिस बल एवं कानून व्यवस्था

- सिटीजन पोर्टल 'हरसमय' 24x7 पर उपलब्ध सभी 14 सुविधाओं का लाभ नागरिक इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर से, साईबर कैफे से या राज्य भर में फैले लगभग 4000 CSCs या 134 ई-दिशा केन्द्रों से ले सकते हैं।
- बलात्कार के मामलों की जांच एक महीने में पूरी करने व छेड़छाड़ तथा यौन उत्पीड़न के मामलों में 15 दिन के अन्दर जांच पूरी करने के आदेश जारी।
- सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग की सड़क सुरक्षा निधि स्वीकृत।
- एन.आर.आई. की शिकायतों के निपटान हेतु एन.आर.आई. सैल हरियाणा पुलिस विभाग की वैबसाईट पर लांच किया।
- पहली बार सभी पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश शुरू।
- असामाजिक तत्वों के साथ मुठभेड़ में शहीद व गंभीर रूप से घायल होने पर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि को क्रमशः 10 लाख व 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख व 15 लाख रुपये करने की घोषणा।
- पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की वर्तमान संख्या 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.haryanapoliceonline.gov.in
2. दूरभाषः— 0172—2587529

सिटीजन पोर्टल 'हरसमय' 24x7 शुरु
लोग घर से ही शिकायत या
एफ.आई.आर. दर्ज करवा सकते हैं

जीरो एफ.आई.आर.
प्रदेश के किसी भी थाने में
एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा सकती है,
चाहे घटना कहीं भी घटित हुई हो

पुलिस विभाग द्वारा
14 पुलिस पब्लिक स्कूल
चलाये जा रहे हैं

भ्रष्टाचार पर लगा अंकुश, हर नागरिक हुआ खुश

- भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टोलरैंस' की नीति पर अटल सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने के लिए विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 391 आपराधिक मुकद्दमे दर्ज।
- राज्य सतर्कता ब्यूरो ने जन साधारण को शिकायतें भेजने के लिए Whatsapp Number 9417891064 उपलब्ध करवाया।
- राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा 281 नई जाचें दर्ज, जिनमें से पंचकूला कौशल्या बांध घोटाला, पंचकूला शामलात जमीन घोटाला, पंचकूला औद्योगिक प्लाट आवंटन घोटाला, पिल्लर बॉक्स घोटाला, पांच सितारा पुल मैन होटल को रास्ता देने का घोटाला, एच.सी.एस. की नियुक्ति में अनियमितताएं, अम्बाला का मनरेगा घोटाला व एन. आई.टी. फरीदाबाद में 8012 वर्ग गज सरकारी जमीन घोटालों की जांचें शामिल हैं।
- सभी विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त।
- सरकार का उद्देश्य 'शासन कम से कम-सुशासन अधिकतम' के सिद्धान्त के मद्देनज़र मानव हस्तक्षेप को कम करके, बड़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.haryanavigilance.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2970218

भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करवाने के लिए

टोल फ्री चौकसी
हेल्पलाइन नम्बर 1064
टोल फ्री नम्बर 1800-180-2022

जिला एवं उप-मण्डल स्तर पर सी.एम. विंडो स्थापित,

अब तक 3,18,928 प्राप्त शिकायतों, मांगों और सुझावों में से
2,63,369 का समाधान

अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता व पारदर्शिता

- 'स्वर्ण जयन्ती वित्त नीति संस्थान' नामक एक राज्य स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने हेतु वर्ष 2016-17 में 5 करोड़ रुपये तथा 2017-18 में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- वर्ष 2016-17 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर 8.7 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित।

कर्मठता के प्रतीक कर्मचारी

- पहली जनवरी, 2017 से अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय।
- पारिवारिक पेंशन में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी।
- सभी सफाई कर्मचारियों के लिए हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा।
- सभी नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्ग का बैकलॉग पूरा करने की घोषणा।
- दिल्ली स्थित प्रदेश कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों का मकान भत्ता 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया।
- सेवा अवधि के दौरान एडहॉक, अनुबंध व डी.सी. रेट पर लगे कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को तीन लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि देने का प्रावधान।
- एक्सग्रेसिया पॉलिसी का लाभ अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गैस्ट टीचर्स को भी मिलेगा।
- प्रदेश में कार्यरत डॉक्टरों की सेवानिवृति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय।
- "पुलिस भर्ती में पारदर्शिता" (टी.आर.पी.) पद्धति लागू की गई।

☞ और जानकारी के लिए देखें

1. www.csharyana.gov.in
2. दूरभाषः– 0172–2740118

यू.पी.आई., यू.एस.एस.डी. और ई-वॉलेट में से किसी एक में पंजीकृत नागरिकों को कम से कम एक लेन-देन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने पर 5 रुपये की प्रोत्साहन राशि उनके खाते में जमा करवाई जाती है

'भीम' ऐप के माध्यम से कैशलैस लेन-देन

सातवां वेतन आयोग लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य

महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव के लिए अर्जित अवकाश की शर्तों में छूट

CM WINDOW

म्हारा हरियाणा-सम्मानित हरियाणा

विभिन्न क्षेत्रों में मिले राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार

1. बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए "Best Horticulture State Award".
2. चावल उत्पादकता के लिए 'कृषि कर्मण' पुरस्कार।
3. ई-शासन प्रणाली के बेहतर इस्तेमाल के लिए 'स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस' अवार्ड-2015 से सम्मानित।
4. वर्ष 2015 में 'एक्सिलेंस ऑफ सी.एस.आई. नीहिलेंट' अवार्ड।
5. 28 दिसंबर, 2015 को 'डिजिटल इंडिया' अवार्ड।
6. ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए 5 नवम्बर, 2016 को 'बेस्ट इम्प्रूवड स्टेट इन ई-गवर्नेंस' अवार्ड।
7. लिंगानुपात सुधार के लिए 'नारी शक्ति पुरस्कार 2015 (कानगी देवी) अवार्ड।
8. शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए प्रथम पुरस्कार।
9. छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित।
10. पिराई सीजन 2015-16 के लिए शाहबाद सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में प्रथम पुरस्कार।
11. पिराई सीजन 2015-16 के लिए करनाल सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में द्वितीय पुरस्कार।
12. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 5 अवार्ड।

हरियाणा देश में अग्रणीय राज्य

1. गन्ने का भाव 320 रुपये प्रति क्विंटल तक, देश में सर्वाधिक।
2. देश का पहला राज्य, जहां देसी गाय का पास्चुरीकृत 'ए-2' दूध वीटा बूथों पर उपलब्ध।
3. पहला प्रमुख राज्य, जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से शत-प्रतिशत पेंशन लाभार्थियों के खाते में।
4. वर्ष 2016-17 में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1,80,174 रुपये रहने का अनुमान है, जो कि देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है।
5. ओलम्पिक खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि देश में सर्वाधिक।
6. बेरोजगार युवाओं के लिए देशभर में अपनी तरह की पहली अनूठी सक्षम युवा स्कीम शुरू।
7. देश का पहला डिज़िटल जांच, प्रशिक्षण एवं विशलेषण केंद्र गुरुग्राम में स्थापित।

8. सातवें वेतन आयोग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य।

9. देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केन्द्र 'नन्दघर' गांव हसनपुर जिला सोनीपत में।

10. देश की पहली सी.एन.जी. आधारित डी.ई.एम.यू. रेल सेवा रेवाड़ी से रोहतक के बीच शुरू।

11. अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबन्धन (ISA) का वैश्विक सचिवालय गुरुग्राम में।

12. केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का योगदान देने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य।

13. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 878 ग्राम दूध उपलब्धता के साथ देश में दूसरे स्थान पर।

14. उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान (एन.आई.डी.), कुरुक्षेत्र में स्थापित।

15. पहली बार व्यापारियों के लिए ई-रिफंड की ऑनलाईन सुविधा।

16. पहली बार मूंग की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर।

17. पहली एन.सी.सी. अकादमी घरोंडा, जिला करनाल में खोलने की मंजूरी।

18. Ease of Doing Business में हरियाणा 14वें स्थान से पहुंचा छठे स्थान पर।

19. ''नीति आयोग'' की रिपोर्ट के अनुसार कृषि बाजार और किसानों के अनुकूल सुधार करने के मामले में हरियाणा पांचवें स्थान पर।

20. ऐसा राज्य जहां होटल प्रबन्धन से संबंधित पांच संस्थान कार्यरत हैं।

21. प्रदेश में पहली बार सभी पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश शुरू।

प्रदेश को मिले कई अवार्ड एवं पुरस्कार

बनी 'डिजिटल हरियाणा' की अनूठी मिसाल

- वर्ष-2016 में भूमि के ई-पंजीकरण के क्षेत्र में ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- ई-शासन में जी.आई.एस.टैक्नोलोजी के अनूठे उपयोग के लिए जिला प्रशासन गुरुग्राम की जी-त्रिकोणीय परियोजना के लिए जनवरी-2017 में ''नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड-गोल्ड आर्डर''।
- नवजात शिशुओं के जन्म के समय ही आधार पंजीकरण के लिए ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड'' तथा ''फर्स्ट स्टेट आफ इंडिया अवार्ड''।
- ई-टूरिज़्म पर्यटन सुविधाओं की ऑनलाईन बुकिंग तथा समेकित वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के लिए ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- सी.एम. विंडो के माध्यम से जन शिकायतों के निवारण के लिए ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड'' तथा ''स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड''।
- हरियाणा की ई-शासन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। राज्य श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित अवार्ड 'एक्सिलेंस ऑफ सी.एस.आई. नीहिलेंट' अवार्ड।
- डीलर्स प्रबन्धन के लिए ई-एप्लीकेशन, रिटर्नस की ई-फाईलिंग, सी-फार्म इत्यादि के लिए ''स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड'' व ''स्कॉच आर्डर आफ मैरिट अवार्ड''।
- हरियाणा को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए ''श्रेष्ठ उन्नत राज्य के लिए ई-गवर्नेंस अवार्ड''।
- कैशलैस लेन-देन की पहल करने के लिए ''डिजिटल इंडिया अवार्ड''।
- ई-स्टैम्पिंग के साथ ई-ग्रास का एकीकरण के लिए ''सी.एस.आई. निहिलेंट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस''।
- 'थारी पेंशन-थारे पास योजना' के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण के लिए सितम्बर, 2016 को ''स्मार्ट गवर्नेंस गोल्ड अवार्डस'' व ''स्कॉच ऑर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड''।

सी.एम. खट्टर ने दिया प्रकृति से प्रेम करने का संदेश

'प्रकृति को संजोकर रखने की जरूरत'

सफाई अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने गांव की गलियों व सड़कों पर ग्रामीणों के साथ लगाया झाड़ू

अब शहादत के सम्मान में दस्तावेज नहीं बनेंगे रोड़ा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी

कलस्टर आधार पर लागू किया जाएगा, जुलाई तक नामांकन

लीडिंग ऑफ डिवेलप्ड इंडिया फेस्ट के दूसरे दिन किया संबोधित

विकसित देश बनने की ओर बढ़ रहा है भारत : विज

सींचेवाल मॉडल पर प्रदेश में होगा जलशुद्धिकरण

यमुनानगर के दर्जनभर गांवों में योजना, गांव खेमकलां में पहला संयंत्र लगाने की तैयारी

गांवों को लाभ मिलेगा

प्रदेश में आज से ये बदलाव होंगे

किसानों की हर कठिनाई का समाधान होगा :खट्टर

हुड्डा सरकार द्वारा बनाए गए चार एग्रो मॉल बेचे जाएंगे

कार्यकर्ताओं से बातचीत करते मुख्यमंत्री मनोहरलाल।

दैनिक सवेरा

Wed, 21 June 2017

प्रदेश की 6205 पंचायतें खुले में शौचमुक्त हुईं

जीएसटी नियम मंजूर

कल्याणकारी योजनाओं की
जीती-जागती कहानी-चित्रों की जुबानी
जनता के मुख से

''मैं खाना बनाती थी, तो धुंए से बेहद परेशान रहती थी। इसके कारण मेरे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। मैं सपने में सोचा करती थी कि क्या मेरे घर में भी मेरा अपना गैस कनैक्शन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आखिरकार वो दिन दिखाया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार होने के कारण मुझे अपना मुफ्त में गैस कनैक्शन मिला।''

सीमा
गांव कैरवाली, जिला करनाल

''मनोहर सरकार ने पेंशन में जितनी बढ़ोतरी की है उतनी किसी भी सरकार ने नहीं की है। मुझे हर महीने 1600 रुपये पेंशन मिलती है, जिससे मैं छोटे-छोटे खर्चों के लिए अब अपने बच्चों पर निर्भर नहीं हूं और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, कि पेंशन सीधे मेरे खाते में आती है।''

बाबूराम शर्मा
गांव शेखपुरा, जिला करनाल

''मैंने बागवानी विभाग की मदद से एक एकड़ में पॉली हाउस स्थापित किया है, जिसमें 35 प्रतिशत राशि मैंने लगाई है तथा 65 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान के रूप में मिली है। मैं पॉली हाउस में टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च आदि सब्जियों का उत्पादन करता हूं, जिस से मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। मेरे पॉली हाउस में जल संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में टपका विधि से सब्जियां उगाई जाती हैं। जिससे हम खेती करने से 10 गुणा तक पानी की बचत कर सकते हैं और जल स्तर को बढ़ा सकते हैं।''

फूल सिंह,
गांव जयसिंहपुरा, जिला करनाल

''पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करके व शैक्षणिक योग्यता लागू करने से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। शिक्षित पंचायतें विकास कार्यों की समीक्षा करने में अधिक सक्षम हैं। सरकार का ये फैसला सराहनीय है।''

नीलम
गांव कलियाणा, जिला भिवानी

''देशभर में लागू कैशलेस योजना सराहनीय है। इससे न तो खुले पैसों का झंझट रहता है, न ही जेब कटने का डर। कैशलेस से दुकानदार भी सुरक्षित तथा ग्राहक भी सुरक्षित रहता है। वे स्वयं अधिक से अधिक कैशलेस योजना के माध्यम से ही सामान बेचते हैं और आम लोगों को भी प्रेरित करते हैं।''

दिनेश कुमार एवं राजेश कुमार
गांव सिवानी, जिला भिवानी

''सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना अपनाकर पूरा गांव खुश है। सारा दिन बिजली रहने से ना तो घर के काम प्रभावित होते हैं और बच्चे रात को आसानी से पढ़ाई-लिखाई कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि हर गांव को इस योजना से जुड़ना चाहिए और बिजली बचत के साथ-साथ समय पर बिजली के बिलों की अदायगी भी करनी चाहिए।''

बबीता देवी, सरपंच,
गांव ढाणी, जिला भिवानी

''हमें अब गांवों में ग्राम सचिवालयों की स्थापना से प्रमाणपत्रों के संबंध में गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता। इससे आमजन को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब हमें छोटे-छोटे कामों के लिए अपनी खेती के काम को छोड़कर शहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। सरकार का यह कदम बहुत सराहनीय है।''

हरभगवान
गांव किरावड़, जिला भिवानी

"सी.एम. विंडो से लोगों की समस्याओं का समाधान तत्परता से होने लगा है। इससे न केवल आमजन को राहत मिली है, बल्कि प्रशासन भी चुस्त हुआ है और पहले से अधिक जवाबदेह हुआ है। सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली की बात की जाए तो पीओएस मशीन से गरीबों का राशन गरीबों को ही मिलना संभव हुआ है। लोगों को घरेलू गैस आसानी से उपलब्ध होने लगी है और इसमें हेराफेरी की गुंजाईश नहीं रही है।"

भोपाल सिंह सरोहा
एडवोकेट, जिला भिवानी

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। फसली नुकसान के चलते सरकारें मुआवजा राशि का वितरण करती रही हैं लेकिन इसका फायदा सीधे किसानों को न मिलकर बीच के दलाल की जेबों में पैसा जाता रहा है। अब किसान को सीधा फायदा मिलेगा, वहीं पिछले दिनों वर्तमान सरकार ने रिकार्ड दिनों में मुआवजे का वितरण किया जो एक उदाहरण है, इससे साबित होता है कि सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है।"

राजेन्द्र सिंह
गांव हसान, जिला भिवानी

"गैस कनैक्शन मिलने से पहले मिट्टी के चूल्हे पर बरसात के दिनों में लकड़ी व उपले गीले होने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नए गैस कनैक्शन से मुझे धुएं से निजात मिली है। इससे हमारा रहन-सहन भी बदला और साथ-साथ समय की बचत भी हुई है।"

सीता देवी
गांव नौंच, जिला कैथल

"सरकार तो किसानां की भलाई के काम करन में ओरां तै घणी आगे कढगी। जिन गामां मैं खेतां ताईं पाणी ना आवै था आज इस सरकार ने उनके खेतां मैं पानी देकर उनकी फसलां की पैदावार ए बढ़ा दी। इतने ए कोनी उनकी फसल के ढाडे दाम लगाकै सरकार ने म्हारा मान बढ़ाया है। घणी बरसात और ओले पडन पै भी नुकसान की भरपाई सबतै ज्यादा मुआवजा देकै की सै। फसल बीमा योजना तै भी किसान इब खेत में होन आले नुकसान की चिंता छोड़ रहा सै। इस सरकार नै किसानां खातर घणी योजना चलाई सैं अर हम उनका पूरा फायदा ठावैंगे।

सतनारायण और कृष्ण फौजी
गांव मंडवाल, जिला झज्जर

''हैपनिंग हरियाणा, प्रवासी हरियाणा दिवस के साथ ही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के औद्योगिक संभावनाओं के मद्देनजर किए गए विदेश दौरों ने हरियाणा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने में सकारात्मक कदम उठाए हैं। बहादुरगढ़ औद्योगिक नगरी के रूप में निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और के.एम.पी. एक्सप्रेस हाईवे के साथ बेहतर कॉरिडोर विकसित होने से यह क्षेत्र उद्यमियों के लिए बेहतर पसंद बनने जा रहा है। उद्यमियों को निवेश के सुअवसर प्रदान हों इसके लिए बेहतर औद्योगिक वातावरण देने के साथ ही सुविधाजनक प्रक्रिया भी उद्योगपतियों को उपलब्ध कराई जा रही है।''

अशोक गुप्ता
उद्यमी एवं चेयरमैन, गणपति धाम औद्योगिक क्षेत्र, बहादुरगढ़

''किसी आपदा के समय ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता था लेकिन वर्तमान सरकार की बीमा योजनाओं विशेषकर प्रधानमंत्री बीमा एवं पशुओं व फसल के लिए बीमा योजनाओं से ग्राम जोखिम मुक्त बनने की ओर अग्रसर हुए हैं। जोखिम मुक्त गांव बनने से गांव में लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है।''

महेन्द्र सिंह
सदस्य, ग्राम पंचायत गांव उखलचना (कोट)

'' कृषि कार्य के प्रति पहले युवाओं के लिए अरूचिकर होती थी लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से गुरुग्राम व फरीदाबाद में आयोजित हुए एग्रो लीडरशिप सम्मिट ने युवाओं के नजरिए को बदल कर रख दिया। खेत से बाजार तक के संबंधों को बेहद सहज व आसानी से इन सम्मेलनों के जरिए अब समझा जा सकता है।''

उपेन्द्र
गांव दुजाना, जिला झज्जर

''स्कूलों को अपग्रेड करना सरकार का एक सराहनीय कदम है। नारायणगढ़ क्षेत्र में दसवीं के दो स्कूलों को अपग्रेड कर बारहवीं का दर्जा दिया गया है जिससे बच्चों को पढ़ने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त गांव कुराली तथा पिलखनी के लोग काफी समय से स्कूलों को अपग्रेड करने की मांग कर रहे थे जोकि वर्तमान सरकार में जाकर पूरी हुई है। गांव बडागढ़ में राजकीय महिला कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।''

पंकज शर्मा
गांव हमीदपुर, जिला अम्बाला

"शिक्षित पंचायतें होने से अब गांव का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। विकास के अलावा सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव हुआ है। इस बार पंचायती राज संस्थाओं को युवा और गतिशील नेतृत्व मिला है जोकि शिक्षित पंचायतों के कारण ही सम्भव हो पाया है। जब पंचायत प्रतिनिधि पढ़े लिखे होते हैं तो उन पर अधिकारियों/कर्मचारियों का अनावश्यक दबाव भी नहीं रहता और वे अपने गांव की समस्याओं को सही प्रकार से रख सकते हैं।"

संजू रानी
गांव काठेमाजरा, जिला अम्बाला

"प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याणार्थ अनेक निर्णय लिये हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल बस सर्विस चलाई है। इससे स्कूल, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को आने-जाने में सुविधा हुई है वहीं महिला सुरक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण कदम है। लड़कियों के लिए गांव बडागढ़ में राजकीय कन्या कालेज खोले जाने से अब क्षेत्र की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।"

दीक्षा गर्ग
गांव खानपुर राजपुतान, जिला अम्बाला

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ।।

(श्रीमद्भगवद्गीता 2/47)

मानव को केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मानव के कर्म का उद्देश्य फल–प्राप्ति कभी नहीं होना चाहिए और न ही कर्म के त्याग के प्रति मानव अनुराग होना चाहिए।